



न्यूज डायरी

## इरफान की फिसली जुबान राहुल को स्वर्गीय कह दिया

रांची। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। लड्डू बांटे। जश्न मनाते के दौरान जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर उत्साह ऐसा चढ़ा कि बोलते बोलते उन्होंने अपने राहुल गांधी को स्वर्गीय राहुल गांधी कह दिया। हालांकि सामने खड़े लोगों ने उन्हें उनकी गलती का एहसास भी करा दिया।

## हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश की सीएजी रिपोर्ट

रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को भाजपा के हंगामे के बीच वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन के फ्लोर पर सीएजी की रिपोर्ट रखी।

## आतंकी साजिश: एनआइए ने घाटी में छापामारी की

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आतंकी साजिश मामले में शुक्रवार को कश्मीर में पांच स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ये छापेमारी घाटी के कई जिलों में चल रही है। यह मामला भौतिक और साइबरस्पेस दोनों में एक साजिश रचने और प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठनों द्वारा जम्मू-कश्मीर में चिपचिपे बम, आईईडी और छोटे हथियारों के साथ हिंसक आतंकवादी हमले करने की योजना से संबंधित है।

## आदिवासी महोत्सव में गुंजेगी मोनिका की सुरीली आवाज

रांची। झारखंड की स्वर कोकिला कही जाने वाली मोनिका मुंडू आदिवासी महोत्सव में कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मोनिका मुंडू ने फोलोरा, नदिया किनारे, न्यारी, हंसा जोड़ी जैसी कई हिट नागपुरी म्यूजिक एल्बम में स्वर दे चुकी हैं। अभिनय की दुनिया में भी उन्होंने अलग पहचान बनायी है।

## पाक ने ड्रोन से गिराये 53 करोड़ की हेरोइन

नयी दिल्ली। पाकिस्तानी तस्करी ने गुरुवार देर रात ड्रोन के जरिये 53 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप भारत में भेजी। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। इलाके में सघन अभियान चलाया जिसमें 3 पैकेट रात में ही बरामद किए गए और चौथा पैकेट शुक्रवार सुबह बरामद किया है। पाकिस्तानी ड्रोन को मार भगाया। हेरोइन का वजन 10 किलो 850 ग्राम है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 53 करोड़ है।

बाहना	आभूषण
खोना (बिक्री) : 55,900 रु./10 आम चांदी	: 74,000 रुप/पति किलो

## आज जारी होगा आकलन परीक्षा का आंसर की और ओएमआर शीट

## खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव

रांची। झारखंड अधिविध परिषद (जैक) आकलन परीक्षा का आंसर की कल जारी करेगा। साथ ही ओएमआर शीट भी जैक की साइट पर अपलोड करेगा, ताकि राज्य के 43000 जैसे परीक्षा शिक्षक जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है, उन्हें पता चल सके कि वे कितने पानी में हैं। जैक की ओर से पहली बार परीक्षा आयोजित करने के बाद पूरी ओएमआर शीट को ही पोर्टल पर सार्वजनिक किया जा रहा है। इसके साथ साथ आंसर की जारी कर उन्हें यह बताने का प्रयास किया

## अंतिम दिन 45 बिल समेत स्वास्थ्य विज्ञान विवि विधयेक पास मुख्यमंत्री होंगे कुलाधिपति

► **मानसून सत्र के आखिरी दिन 45 प्राइवेट बिल पारित**  
► **विनोद सिंह में उठाया कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मुद्दा**

## खबर मन्त्र व्यूरे

रांची। विधानसभा में शुक्रवार को भोजनवकाश के बाद हंगामे के बीच झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधयेक 2023 पारित कर हो गया। हेल्थ साइंस के संसाधनों को राज्य में समृद्ध करने के उद्देश्य से यह विधयेक लाया गया है। यूनिवर्सिटी के जरिये राज्य में हेल्थ साइंस की पेशेवर शिक्षा को विकसित किया जायेगा। इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, दंत चिकित्सा, फीजियोथेरेपी, पारा मेडिकल समेत कई विषयों की पढ़ाई होगी। रिसर्च से जुड़े विषयों को सुविधाजनक बनाया जायेगा। विधयेक में प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होंगे। सीएम ही दीक्षांत समारोह और शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। विश्वविद्यालय में कुलपति, डिपार्टमेंट के डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक समेत कई पदों का सृजन होगा। पहले कुलपति की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जायेगी। 70 वर्ष से कम उम्र के ही व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किया जायेगा।



## सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार दूंगा : सीएम

मानसून सत्र के अंतिम दिन समाप्त अभिभाषण में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में हम नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ा चुके हैं और यह लगातार जारी रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार व स्वरोजगार दूंगा। उनकी सरकार विधि-व्यवस्था बनाये रखने को कृतसंकल्प है। पुलिस को अपराध पर नियंत्रण की खुली छूट है। मणिपुर में आदिवासी समाज का उन्नीचन हो रहा है पर केंद्र व वहां की सरकार मूकदर्शक है। सीएम ने कहा कि वन संरक्षण नियमावली में पिछले वर्ष ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया गया और फिर लोकसभा के सत्र में वन संरक्षण कानून में केंद्र सरकार ने ऐसे संशोधन किये गये कि भविष्य में आदिवासियों से उनका जंगल ही छीन लिया जायेगा। इसे यहां लागू नहीं होने दूंगा।

## बकाया वसूली को ले लोक उपक्रमों पर सर्टिफिकेट केस : डॉ उरांव

रांची। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार और लोक उपक्रमों पर राज्य का भारी-भरकाम पैसा बकाया है। इसे प्राप्त करने की विधिवत कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसके लिए किसी तरह के असंवैधानिक कदम नहीं उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोक उपक्रमों के बकायों की वसूली के लिये सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर

## झारखंड सरकार भी जाति जनगणना के पक्ष में

रांची। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को सदन में कहा कि झारखंड सरकार पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने और जातिगत जनगणना कराने को लेकर गंभीर है। सरकार भी चाहती है कि राज्य में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सदन में इसे पारित कर केंद्र को भेजा जायेगा। यदि केंद्र इसे मंजूरी नहीं देता है, तो भी बिहार की तर्ज पर राज्य में इसे लागू करने पर विचार किया जायेगा। दरअसल, शुक्रवार को प्रथम पाली में विधायक प्रदीप यादव ने यह मामला उठाया था। प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये सरकार से पूछा था कि राज्य में पिछड़ों की

लोक उपक्रमों के पास बकाया है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में करीब 22 सौ करोड़ से अधिक की राशि बकाया है। राज्य सरकार के प्रयास से भूमि अधिग्रहण मद में 2532.55 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म मद में 80 हजार करोड़, कॉमन कॉज मद में 35 हजार करोड़ रु, बिजली विभाग के 1779 करोड़ समेत अन्य मद में भारी भरकम राशि बकाया है। इसको लेकर कोयला मंत्रालय समेत केंद्र के अन्य उपक्रमों से कई बार बातचीत हुई है। कोयला मंत्रालय ने कोल बेयरिंग एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि जमीन पर उसका हक है। इस डाउट को समाप्त करने पर उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरफेस लैंड पर राज्य का हक होता है। जबकि सरफेस के नीचे की जमीन केंद्र की होती है। कोयला मंत्रालय को यह बात समझ में आ गई है। इसके बाद वहां से कहा गया कि कमर्शियल रेट पर पैसे नहीं देंगे। इसको राज्य सरकार ने मान लिया है और कृषि रेट पर ही बकाया देने की मांग की है। इसको लेकर ज्वाइंट सर्वे कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद डिमांड तय होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास बकाया राशि की वसूली के लिये वैधानिक तरीका मौजूद है। यह सभी जानते हैं कि सर्टिफिकेट केस से विलंब होता है। यह भी समझना चाहिये कि केंद्र की कंपनियां पर केस करना चाहिए या नहीं। इसलिए हम नीति आयोग के पास गये। उन्होंने भरसा दिलाया कि केंद्र सरकार और उसके अन्य उपक्रम बकाया राशि को धीरे धीरे लौटावेंगे।

प्रदीप यादव ने उठाया था मामला : दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान सदन में विधायक प्रदीप यादव ने बकायों की वसूली संबंधी सवाल पूछा था। डॉ उरांव ने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि केंद्र अगर बकाया नहीं देगा तो कोयले की दुलाई भी बंद की जा सकती है। चक्का जाम किया जा सकता है। ऐसी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं। इशारों-इशारों में वित्त मंत्री ने कहा कि

ऐसा होने से झारखंड को भी क्षति होगी। श्री यादव ने पूछा था कि केंद्र सरकार के पास बकाया राशि और केंद्र की योजनाओं के मद में 35 हजार करोड़ रुपये के लिए बार-बार मांग करनी पड़ रही है। वसूली के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। 35000 करोड़ से अधिक बकाया: वित्त मंत्री : इसके जवाब में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 35000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार और

## सुभाष मुंडा के परिजनों को मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा सरकार आपके साथ है कोई अपराधी नहीं बचेगा

## खबर मन्त्र व्यूरे

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को सुभाष मुंडा के माता-पिता को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर हाल में आपके परिवार को न्याय देगी। किसी भी हाल में इस हत्याकांड में सलिलन अपराधियों को बक्शा नहीं जायेगा। सीएम ने कहा, मैंने स्वयं इस हत्याकांड को गंभीरता से लिया है। सरकार के निर्देशानुसार पुलिस स्व सुभाष मुंडा की हत्या से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। मैं खुद पूरी जानकारी लेते रहता हूँ। उन्होंने परिजनों से कहा कि राज्य सरकार परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जायेगी।

स्व सुभाष मुंडा के परिजनों ने सीएम से शुक्रवार को भेंट की और अपनी गुहार लगायी और मदद का



## दलादली चौक में बनेगा पुलिस आउटपोस्ट

मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि जल्द ही दलादली चौक के समीप पुलिस आउटपोस्ट स्थापित होगा। वहां प्रकाश की व्यवस्था भी की जायेगी। हाल के दिनों में रिंग रोड स्थित चौराहों पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता दिख रहा है। राज्य सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन को इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध नियंत्रण पर कार्य कर रही है। परिजनों में सुरेश मंडा, अमित मुंडा, बिशु मुंडा सहित जेएमएम नेता मुश्ताक आलम एवं अन्य उपस्थित थे।

अनुसूध किया। सीएम श्री सोरेन ने स्व मुंडा के माता-पिता एवं पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। (शेष पेज 11 पर)

## गृह सचिव अजय भल्ला को भी फिर सेवा विस्तार

नयी दिल्ली। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को सरकार ने लगातार चौथा सेवा विस्तार दिया है। वह इसी महीने की 22 तारीख को सेवामुक्त होने वाले थे, लेकिन उन्हें भी अब 22 अगस्त, 2024 तक विस्तार दे दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौवा के बाद एक और बड़े अफसर को केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को सरकार ने लगातार चौथा सेवा विस्तार दिया है। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजय कुमार भल्ला के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। उन्हें अगले साल 22 अगस्त तक के लिए एक्सटेंशन मिला है। अजय भल्ला को नवंबर 2020 में ही रिटायर होना था, लेकिन उनके कार्यकाल को सरकार ने अक्टूबर 2020 में 22 अगस्त, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था।

## राहुल की संसद सदस्यता होगी बहाल मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

## एजेंसी

नयी दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली दो साल की उनकी सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत : सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की (न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार) की पीठ ने कहा कि मानहानि के अपराध के लिए अधिकतम दो साल की कैद की सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका बयान गुड टेस्ट में नहीं था। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। उन्हें (राहुल गांधी) अधिक सावधान रहना चाहिए था। निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गयी थी। सत्य और लोकतंत्र की जीत : कांग्रेस : इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सत्य और लोकतंत्र की जीत है। आज प्रजातंत्र और संविधान की जीत हो गयी। सत्यमेव जयते की जीत हुई है। हमलोग



खुश हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। देश में अभी संविधान जिंदा है और न्याय मिल सकता है, इसकी उम्मीद कायम है। यह सारे भारत की जनता की जीत है। राहुल के खिलाफ जब फैसला आया था, तब मोदी सरकार ने उन्हें हटाने में 24 घंटे का भी समय नहीं लिया था, आज हम देखेंगे कि सरकार उनकी सदस्यता कितने देर में बहाल करती है। सदन में भाग लेंगे कांग्रेस नेताओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि जब तक राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, और कोर्ट

## राहुल बोले सच्चाई की होनी ही थी जीत

सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद राहुल गांधी मीडिया से बातचीत में कहा कि आज नहीं तो कल या परसो सच्चाई की जीत होनी ही थी। उन्होंने कहा कि मुझे आगे क्या करना है ये उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता से जो प्यार और समर्थन मिला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। राहुल ने एक टवीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा, चाहे जो भी हो, उनका प्रयास जारी रहेगा।

अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता है, तब तक के लिए उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जायेगी। अब राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वাস प्रस्ताव पर होने वाले बहस में भाग लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश की प्रति लोकसभा सचिवालय को भेजी जायेगी। लोकसभा सचिवालय को इस पर फैसला लेना होगा। प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत संभव है कि राहुल गांधी मंगलवार को संसद सत्र में शामिल हो जायेंगे।

## झारखंड के 20, बिहार के 49 स्टेशनों का होगा पुनरुद्धार

## पीएम 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की कल रखेंगे आधारशिला

## एजेंसी

नयी दिल्ली। पीएम मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत छह अमृत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गयी। पीएम मोदी जिन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे उनमें झारखंड के 20, बिहार के 49 और पश्चिम बंगाल के 37 स्टेशन शामिल हैं। परियोजना की लागत 24,470 करोड़ रुपये होगी और इससे यात्रियों



को आधुनिक सुविधाएं प्रदान होंगी। इसके लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गयी है। विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी : पीएमओ ने कहा कि मोदी अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते हैं और रेलवे लोगों के परिवहन का पैसंदीदा साधन है। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व को प्राथमिकता दी है। 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 'अमृत भारत

स्टेशन योजना' शुरू की गयी है। इस योजना के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री द्वारा 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी जा रही है। पीएमओ के अनुसार शहर के दोनों किनारों के समुचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह एकिकृत दृष्टिकोण शहर के समग्र शहरी विकास के समग्र दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो रेलवे स्टेशन के आसपास केन्द्रित है। यूपी के सर्वाधिक 55 स्टेशन : पीएमओ के अनुसार जिन स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जानी है इनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55-55 स्टेशन हैं। (शेष पेज 11 पर)

## पांच डीएसपी बदले, बीएन सिंह बेरमो डीएसपी

रांची। पांच डीएसपी का तबादला किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार की देर शाम झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार लोहरदगा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित बीएन सिंह को बोकारो जिले के बेरमो का डीएसपी बनाया गया है। जैप-5 के डीएसपी के पद पर पदस्थापित सुमित प्रसाद को गिरिडीह जिले के डुमरी का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। जय प्रकाश नारायण चौधरी को गोड्डा का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत सुदर्शन कुमार आरितिक को एसीबी रांची का डीएसपी और एसीबी डीएसपी के पद पर पदस्थापित अरविंद कुमार सिंह को विशेष शाखा का डीएसपी बनाया गया है।









## जन् विश्वास?

सं सद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक पारित हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञापित के अनुसार विधेयक का उद्देश्य 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव कर जीवन और व्यापार को सुगम बनाने को बढ़ावा देना है। जब यह विधेयक कानून बन जाएगा तब यह कई कारोबार से जुड़े उद्यमियों के जीवन को आसान बना देगा और दवा उद्योग भी इनमें से एक है। जन विश्वास कानून के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (डीएंडसी) अधिनियम में कुछ बदलावों का दवा निमाता स्वागत करेंगे लेकिन भारत के दवा उपभोक्ताओं के पास खुश होने की कोई बड़ी वजह नहीं है। लोकसभा में इस विधेयक को मतदान के लिए पेश किए जाने से पहले, भारतीय दवा उद्योग की दवा तैयार करने और गुणवत्ता से जुड़ी नियंत्रण कार्यप्रणाली कड़ी जांच के दायरे में आई। इस साल अप्रैल के अंत में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के निरीक्षण के ताजा चरण में एंटासिड, एंटीबायोटिक्स और रक्तचाप कम करने वाली दवाओं सहित 48 आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले और मशहूर ब्रांडों की दवाएं घटिया पाई गई। अमेरिका के यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने भारत के कई प्रमुख दवा निमाताओं की भी खिंचीं की थी जो अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का निर्यात कर रहे थे। उसने इन जेनेरिक दवाओं को बनाने वाले कारखानों में कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई जिनमें अस्वच्छ माहौल में दवा निर्माण, दूषित दवाओं से लेकर अलग-अलग कागजी कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत के एक दवा निमाता द्वारा बनाए गए कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत होने की खबरें भी आईं।

## चावल निर्यात पर रोक

सरकार ने बासमती तथा उसना चावल को छोड़कर हर प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें 11 वर्ष के उच्चतम स्तर पर हैं तथा उनमें और इजाफा होने लगा है। कुछ मामलों में तो जो माल रास्ते में है उसकी कीमत भी 50 से 100 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। भारत पिछले कुछ समय में दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक रहा है और उसने वैश्विक व्यापार का करीब 40 फीसदी अनाज निर्यात किया। वर्ष 2022-23 में उसने 2.23 करोड़ टन चावल निर्यात किया। उसके अचानक इस बाजार से बाहर हो जाने से वैश्विक आपूर्ति में कमी बढ़ करेगी टन की कमी आएगी। गैर खसूबदार चावल के अनिवार्य निर्यातकों में थाईलैंड और वियतनाम के पास इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त चावल का भंडार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो पहले ही मौसम के कारण उपज से जुड़ी अनिश्चितताओं, रूस द्वारा यूक्रेन को काला सागर बंदरगाहों के जरिये अनाज निर्यात की इजाजत वापस लेने के कारण बढ़ी हुई थीं उनमें और तेजी आई है। इससे खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों की चिंताएं बढ़ेंगी। खासतौर पर छोटे अफ्रीकी देशों की जो भारत से आने वाले अनाज पर निर्भर करते हैं। आश्रय नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंध को लेकर आक्रामक रुख दिखाया और कहा कि इससे वैश्विक खाद्य कीमतों की अस्थिरता की स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने भारत से कहा है कि उसे यह प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। देश में भी सरकार के कदम को समझदारी भरा नहीं माना जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक बात तो यह कही जा रही है कि ऐसा करके भारत आकर्षक वैश्विक कीमतों से फायदा उठाने से चूक रहा है।

## रुद्राक्ष की महिमा

**धर्म प्रताह**  
अजय दीप धाववा

रुद्राक्ष धारण करने के कई मानसिक, शारीरिक और मानवीय लाभ हैं। ये न सिर्फ हमें अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं बल्कि योग साधना व मानसिक शांति को बढ़ाने में, अंतर्मन को साफ करने, शरीर के सात चक्रों की सफाई में और नकारात्मक ऊर्जा से बचने में सहायता करते हैं। बच्चे, व्यक्ति, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। पंचमुखी, द्विमुखी, शनमुखी, गौरीशंकर आदि। रुद्राक्ष का प्रयोग सदैव, यथा सोते/ जागते/ कार्यरत रहते, किया जा सकता है। इसे सिर्फ ज्योत्सना से बचना चाहिए। इसे धातु के संपर्क से भी बचना चाहिए। रुद्राक्ष धारण कर मंदिरा या मांस के सेवन से बचना चाहिए।

**कॉर्टून वर्ल्ड**  
गरीबी और शिक्षा...

**लेटर टू एडिटर**

## खतरा भी बढ़ा

मेटावर्स एक परस्पर जुड़ी वर्चुअल दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें लोग वास्तविक नहीं बल्कि वर्चुअल रूप से मौजूद रहते हैं। यह वास्तविक और डिजिटल सच्चाइयों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। यह व्यवसायों, सामाजिक संस्कृति और बातचीत और मनोरंजन के लिए बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। साईड इफेक्ट पर भी ध्यान देना होगा। - रविशंकर सिंह हजारीबाग

## वन का विनाश

विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वनों को उजाड़ा जा रहा है, उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। पिछले साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दवा किया था कि अगर जंगलों को बचाने की पहल तेज नहीं हुई तो 2025 तक देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के छह राज्यों में वन प्रदेश कम हो जायेंगे वन कटना बंद हो जायेगा। - सीमा रांची

## स्कूलों में स्मार्ट फोन के उपयोग पर पाबंदी आवश्यक

फायदों के बावजूद स्मार्टफोन जैसी डिजिटल तकनीकों का बढ़ता दुरुपयोग बच्चों को शिक्षा से दूर ले जा रहा है। किसी नशे की तरह बच्चे इसकी लत का शिकार बनते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने से क्लास में अनुशासन बना रहेगा और बच्चों को ऑनलाइन डिस्टर्ब होने से बचाया जा सकेगा। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक टूल की तरह ही किया जाए। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि पारंपरिक शिक्षण विधियों को पीछे न किये जाए। लोकोपयोग के अनुसार, 10 में से केवल एक माता-पिता सोचते हैं कि कक्षा में फोन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र ने स्कूलों में स्मार्टफोन रखने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है।

इन दिनों कई गतिविधियां ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं क्योंकि यह बहुत सुविधाजनक है। इसमें शिक्षा भी शामिल है। इसी कारण से छात्रों के लिए मोबाइल फोन उनकी शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। जो बातें पहले व्यक्तिगत कक्षाओं के दौरान कक्षा में बताई जाती थीं, उन्हें फोन पर पाठ के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया है, यह बहस बनी हुई है कि क्या मोबाइल फोन छात्रों के लिए अच्छा है या बुरा, क्योंकि मोबाइल फोन सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, बल्कि एक मोबाइल फोन एक छात्र के लिए इंटरनेट की विशाल दुनिया की खिड़की है, जो अक्सर उनकी पढ़ाई से छात्र का ध्यान भटका सकता है। यदि आप एक माता-पिता हैं और अपने बच्चे के लिए स्कूल में प्रवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह आपके ध्यान देने योग्य हो सकता है।

हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। स्मार्टफोन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, बच्चों को घर और स्कूल दोनों जगह शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब उनका उपयोग करना ठीक न हो और ऐसा हो तो वयस्क को आदर्श बनना चाहिए, और उन्हें सुरक्षित, जिम्मेदार और उचित उपयोग के आसपास सीमाओं को लागू करने की आवश्यकता होगी। कोविड-19 महामारी का एक बड़ा साइड इफेक्ट यही रहा है कि उसकी वजह से दुनिया के कई स्कूलों बच्चों को स्मार्टफोन



- डॉ मेरी ग्रेस

हमें यह याद रखना होगा कि स्कूली छात्र आखिरकार बच्चे ही होते हैं और वे लगभग हमेशा पढ़ाई और पाठ्यपत्र गतिविधियों को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि जब उनके हाथ में कोई फोन आता है तो वे उसमें डूब जाते हैं। यह आदत कभी-कभी इतनी खराब हो जाती है कि छात्र जल्द से जल्द अपने फोन पर वापस जाने के लिए पढ़ाई को नजरअंदाज करने लगते हैं।

का उपयोग करना पड़ता है। अब इसकी आदत गंभीर रूप लेने लगी है। इंटरनेट स्पष्ट चीजों से भरा पड़ा है, जिसमें आपत्तिजनक से लेकर रक्तर्जित सामग्री तक शामिल है। जबकि कुछ फोन को पैरेंटल लॉक से बाहरी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, कई फोन में यह सुविधा नहीं होती है, और छात्र आसानी से ऐसी चीजों तक पहुंच सकते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, और उनके लिए उन चीजों का पीछा करना स्वाभाविक है जो उन्होंने पहले नहीं देखी हैं। ज्यादातर मामलों में, बच्चे उस छोटी सी उम्र में वो चीजें देख लेते हैं जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए।

बच्चों के लिए मोबाइल फोन का सबसे आम नुकसान यह है कि उन्हें फोन की लत लग जाती है। हमें यह याद रखना होगा कि

स्कूली छात्र आखिरकार बच्चे ही होते हैं और वे लगभग हमेशा पढ़ाई और पाठ्यपत्र गतिविधियों को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि जब उनके हाथ में कोई फोन आता है तो वे उसमें डूब जाते हैं। यह आदत कभी-कभी इतनी खराब हो जाती है कि छात्र जल्द से जल्द अपने फोन पर वापस जाने के लिए पढ़ाई को नजरअंदाज करने लगते हैं। कोविड महामारी के दौरान करोड़ों लोगों में स्मार्टफोन की लत बढ़ी और इसलिए अब इसके नुकसान की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं।

मोबाइल फोन का ज्यादा उपयोग छात्रों की सीखने नहीं देगा और यह उनकी क्रिएटिविटी को भी एक हद तक मारने का काम करता है। यह शिक्षकों के साथ छात्रों

के के मानवीय संपर्क को भी कम कर देता है। जैसे-जैसे शिक्षा तेजी से ऑनलाइन हो रही है, जहां छात्रों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के कई फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। छात्र अक्सर उन गतिविधियों के लिए अपने मोबाइल फोन पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं जिन्हें वे स्वयं अच्छी तरह से कर सकते थे। इसमें बुनियादी गणना जैसे सरल कार्य शामिल हैं, क्योंकि वे फोन के कैलकुलेटर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। या, कभी-कभी, उन्हें किसी प्रश्नोत्तरी का उत्तर याद नहीं होता है जो उन्हें इसे ऑनलाइन देखने के लिए प्रेरित करता है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए और सामाजिक संपर्क जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

इस बात का गंभीरता और सावधानी से अवलोकन करें कि तकनीक का स्कूलों में उपयोग कैसे हो रहा है। स्कूलों में मानव केन्द्रित दृष्टिकोण की जरूरत है जहां डिजिटल तकनीक एक उपकरण के तौर पर काम करे ना कि हावी हो जा जाए। अगर हम उस समय को देखें जब मोबाइल फोन अभी भी हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से इतनी गहराई से नहीं जुड़े थे, तो हम देखेंगे कि छात्र अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए कई शारीरिक गतिविधियों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि, इन दिनों, 8 में से 4 छात्रों के घर के अंदर रहने और समय बर्बाद करने के लिए अपने फोन का उपयोग करने की अधिक संभावना है।

मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से पूरी दुनिया को एक हाथ की हथेली में लाता है, और इस प्रकार बच्चे खेल या किसी भी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के बजाय अपने मोबाइल फोन स्क्रीन से अधिक चिपके रहते हैं। बच्चों को तकनीक के साथ और उसके बिना दोनों तरह से, प्रचुर सूचना में क्यों उपयोगी है और किस नजरअंदाज करना है, सिखाना होगा। प्रौद्योगिकी कभी भी शिक्षकों का स्थान न ले, बल्कि प्रौद्योगिकी को एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साझा उद्देश्य को हासिल करने में मददगार हो।

**नकल** विधेयक एक काला कानून है जिसे सरकार अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को दबाएगी। छात्रों के विरोध को इस कानून के आड़ में कुचला जाएगा और निर्दोष विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है।

**मेरी माटी, मेरा देश**  
? आइए हम सब हमारे अमर बलिदानियों को याद करते हुए इस अमृत कलश यात्रा विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद नहीं करें।  
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री

**रोचक ट्वीट**  
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होना, युवाओं की अथाह मेहनत और उनके सपनों को ध्वस्त करने जैसा होता। अब यह सब बंद होगा, पेपर लीक करने वाले गिरोह हो जाए सावधान।  
-हेमंत सोरेन, सीएम

## आधुनिक समाज में बढ़ती पाशविकता चिंताजनक।

**सुधांशु कुमार**  
यह गर्व मानव समाज को अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर मिली विजय का गर्व है। यह गर्व भावहीन मनुष्य को भावयुक्त बनाने का है। यह गर्व पशुवत जीवन से मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का है। हिंसक और बर्बरता की रचना पर प्रेम और निर्माण का गर्व है। मानव केवल एक शारीरिक रचना मात्र ही नहीं है, यह मानवीय मूल्यों और भावों का समावेश है। विचारों का समुच्चय है। इसी मानवीय विचार ने समाज को पाषाणयुगीन अस्थव्य, विचारहीन अवस्था से सभ्य और विचारयुक्त अवस्था तक पहुंचाया है। इसी विचार ने मानवीय जीवन की उत्कृष्टता की इबारत लिखी है। इसलिए आधुनिक समाज में मानवीय

मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे कौनसे कारण हैं जो मनुष्यों को पुनः पाशविकता की ओर ले जा रहे हैं। वह कौनसे कारण हैं कि मनुष्यों में पाशविकता की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। मानवता का अवमूल्यन हो रहा है। आधुनिक समाज में ऐसे अनेकों उदाहरण आए दिन घटित हो रहे हैं, जो मनुष्यों में व्याप्त पाशविक प्रवृत्तियों के बढ़ने के संकेत देते हैं। भारत जैसे देश में जहां पशु-पक्षी पेड़-पौधों को भी आदर्श भाव से देखा जाता है। विगत बरसों में घटित घटनाक्रम व्यथित करने वाले है। इन घटनाक्रमों में धर्म, जाति, भाषा और श्रेष्ठता की आड़ में हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया है। ताजा घटना भारत के मणिपुर राज्य की है। इस राज्य से हिंसा के जो चित्र सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगा कि

**सामयिक**  
आधुनिकता की खाल में छुपा मनुष्य मौका मिलते ही अपनी पाशविक प्रवृत्तियों का गंगा नाच करने से नहीं चूकता है। मणिपुर में जारी जाति और धार्मिक हिंसा ने मानवीयता की गरिमा को तार-तार कर दिया। यहां सामूहिक रूप से पाशविक हुए समुदाय ने दो महिलाओं को नग्न अवस्था में न सिर्फ घुमाया इनके गुणगो से छेड़छाड़ करते हुए बलात्कार की घटना को भी अंजाम दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ऐसी अनेकों घटना होने की बात स्वीकार की है। जाति, धर्म की आड़ लेकर पाशविकता के इस प्रदर्शन ने मानवीय मूल्यों को भारी आघात पहुंचाया है। मणिपुर से दिल दहला देने वाले

वीडियो आ रहे हैं। गली-मोहल्लों की सड़कों और नालियों में पड़ी मनुष्यों की सड़ी-गली लाशें मणिपुर में पाशविकता के प्रदर्शन की ऐसी कहानी है, मणिपुर में अमानवीय और बर्बरता ने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। इन घटनाक्रमों ने मानवीय मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। यह मनुष्यों द्वारा की जा रही बर्बरता का काला अभ्यास है। इसी बर्बरता और पाशविकता को छोड़कर मनुष्य मानवीय मूल्यों के स्थापना की कोशिशों में लगा था। वे सभी कोशिशें धाराशाही हो गईं। हम भारत के लोग अफगानिस्तान में पनप रही तालिबानी मानसिकता के विरोध में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तब यहीं बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम अधिक आधुनिक और प्रजातांत्रिक है। जिस शासन में मानव की गरिमा और

उसके सम्मान की रक्षा की जाती है। हमारे भारत में अनेकता में एकता है। अलग-अलग जाति, धर्म, वर्ण, भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। दुनिया को मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने वाले देश के एक प्रान्त में यह तालिबानी मानसिकता से भी कूट विचार ने कैसे और क्यों जन्म ले लिया। यह सोचने समझने का प्रश्न है। मणिपुर ही नहीं देश में आए दिनों धर्म, जाति, वर्ण की आड़ में यह पाशविक प्रवृत्तियां अपना हिंसक, बर्बर और अमानवीय चेहरा प्रदर्शित करते रहती है। एक पाशविक चेहरा राजस्थान से जून 2022 में वीडियो के रूप में वायरल हुआ था। जब धर्म के अंधे दो अपराधियों ने उदयपुर शहर में एक टेलर की गर्दन को घड़ से अलग कर दिया था।

## वंदे भारत पर करम साधारण ट्रेन पर सितम

## निर्मल रानी

बहुप्रचारित सेमी तीव्र गामी ट्रेन वंदे भारत लगता है रेल मंत्रालय के लिये सफेद हाथी जैसा साबित हो रहा है। अब तक चलने वाली लगभग सभी क्षेत्रों की सभी वंदे भारत ट्रेन्स को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडी दिखाकर रवाना कर इस ट्रेन के बारे में मीडिया व मंहने विज्ञापनों के माध्यम से कुछ ऐसा दिंडोरा पीटा था गोया तीव्रगामी बुलेट ट्रेन ने ही 'वंदे भारत' के रूप में अवतार ले लिया है। शुरूआत से ही 'वंदे भारत' को लेकर अनेक नकारात्मक खबरें आती रही हैं। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत एक्सप्रेस के पूरे रूट में कंटीले तार लगाने का निर्देश दिया था ताकि

## जानवर रेलवे ट्रेक पर नहीं आ पाए। इसके परिचालन के उद्घाटन के

जानवर रेलवे ट्रेक पर नहीं आ पाए। इसके परिचालन के उद्घाटन के लिए सिटी और स्टेशंस की सजावट पर लुटाया जाने वाला जनता का टैक्स का पैसा देखकर ही जब भी यह ट्रेन दुर्घटनाओं या अन्य किसी फाल्ट के चलते खबरों की सुर्खियां बनती हैं तो उस समय सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन की खूब फजीहत होती है। बहरहाल इतनी ढोल पीटकर चलाई जाने वाली यही वन्दे भारत अपने शुरूआती दौर से ही रेल के लिए एक सफेद हाथी साबित हो रही है। इसका अत्यधिक किराया होने व अन्य सुपर फास्ट ट्रेन्स की तुलना में गंतव्य तक पहुंचने के

## समस्या

अंतराल में कोई विशेष फर्क न होने के चलते आम यात्री इसपर यात्रा करना पसंद नहीं कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाली वंदेभारत रेल गाड़ियों में 50 प्रतिशत से लेकर 21 प्रतिशत तक ही सवारियां मिल पा रही हैं जिससे रेल विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए यात्रियों को इन ट्रेन्स में यात्रा हेतु आकर्षित करने के लिये रेल मंत्रालय ने वंदे भारत समेत अन्य कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का किराया घटाने का फैसला किया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वंदे भारत रेलवे बोर्ड वन्दे भारत सहित अनेक ट्रेन्स के अउ चेर्य कार और एक्जीकुटिव क्लास के

किराए में 25% तक की कटौती करने की योजना बना रहा है। लेकिन अतिरिक्त शुल्क जैसे रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट सरचार्ज, जोएस्टी अलग से लगाया जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल उन ट्रेन्स में ही दी जायेंगी, जिन में पिछले 30 दिनों के दौरान केवल 50% सीटें ही भर पाई थीं। रेल मंत्रालय के अनुसार पहले से बुक टिकटों पर यात्रियों को किराए का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा हॉलीडे और फेरिस्टवल स्पेशल जैसी ट्रेनों में यह योजना लागू होगी। गोया एक तरफ तो सरकार विशिष्ट ट्रेन्स में यात्रियों को चलने के लिये उनकी 'चिरोरी' कर रही है उन्हें लुभाने के लिये 25 प्रतिशत तक

**संस्थापक**  
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह  
वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स  
क्वेटेड लिमिटेड के लिए  
मुद्रक, प्रकाशक  
मंजू सिंह  
द्वारा चिरोरी, बोडेया रोड, रांची  
(झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।  
संपादक  
अविनाश ठाकुर\*  
फोन : 95708-48433  
पिन:- 834006  
e-mail  
khabarmantra.city@gmail.com  
R.N.I.No.  
JHAHN/2013/51797  
\*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।



# देश में अब बदल रहा है उर्जा सुरक्षा को लेकर परिदृश्य



अनल कुमार

(डायरेक्टर, अर्थशास्त्री करियर प्लस रांची)

महज 43 फीसदी निर्भरता रखता है। विविधता अपनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र की घटनाएं सरदर साबित होती हैं।

तेल कीमतें और उनका अनुमानित होना भी एक चुनौती है क्योंकि अतीत में तेल आयात बिल में काफी अनिश्चितता देखने को मिली है। इस अनिश्चितता के कारण जीवाश्म ईंधन सब्सिडी या कर राजस्व बजट का निर्धारण करना मुश्किल होता है। वित्त वर्ष 2015 में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी बिल 16.8 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2018 में 9.4 अरब डॉलर था। ऐसे उतार-चढ़ाव औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। खासतौर पर उस समय जबकि कच्चे माल की लागत में ऊर्जा की हिस्सेदारी अधिक हो। आयातित गैस कीमतें एक और पहलू शामिल करती हैं। गैस की अधिकता के कारण एशिया में हाजिर बाजार कीमतें 4 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) हो गई हैं। भारत पूर्व अनुबंध के मुताबिक करत से 85 लाख मिलियन टन गैस 9-10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर लेने को बाध्य है। ऐसे में सौदे की शर्तों पर नए सिरे से चर्चा की बात हो रही है। पेट्रोनेट अमेरिकी कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी ले सकती है, ऐसे में टेलुरियन को कम दरों पर 50 लाख टन गैस मिल सकती है। यह कीमत तय करेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हद तक गैस आधारित होगी।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने में समुद्री सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। भविष्य में इसमें स्थिरता और सीमा पार बिजली ग्रिड की सुरक्षा भी शामिल हो सकती है, बशर्ते कि हम सीमा पार बिजली कारोबार शुरू करें। एक एशियाई सुपरग्रिड को लेकर भारी चर्चा चलती रही है। इसकी अपनी अलग तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां और निहितार्थ हैं। आपूर्ति बाधा कम करने के लिए भारत सामरिक तेल रिजर्व में निवेश करता रहा है। हालांकि सुरक्षित भंडारण की हमारी समझ व्यापक जमीनी बातों से अलग है। बैटरी तकनीक का उदय मौजूद विकल्पों को कई तरह से प्रभावित करेगा। आर्थिक तंत्र के विद्युतीकरण की गति इससे ही निर्धारित होगी। खासतौर पर लाखों सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम जिनके लिए बिजली की खराब गुणवत्ता चिंता का प्रमुख विषय है। ऊर्जा भंडारण, बिजली के मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगा। हाल में सौर ऊर्जा और

भंडारण की सफल बोली की दर ताप बिजली के साथ प्रतिस्पर्धी रही जो उत्पादकता है। वैकल्पिक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी केमिस्ट्री पर इस बात का असर होगा कि हम वितरित बिजली पर कितना भरोसा कर सकते हैं और ग्रिड आधारित व्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सामरिक तेल रिजर्व के अलावा भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था और उन अहम खनिजों के सामरिक रिजर्व के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा जो विभिन्न ऊर्जा भंडारण कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऊर्जा में बदलाव चौथी तरह के जोखिम सामने लाता है जिन्हें वित्तीय रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से लड? के प्रयास कंपनियों की बैलेंस शीट पर जीवाश्म ईंधन भंडार के मूल्य को लेकर संदेह उत्पन्न करते हैं। फार्मेशनल टाइम्स के मुताबिक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने की स्थिति में सरकारी तेल कंपनियों का करीब आधा भंडार बेकार हो जाएगा। कई तेल निर्यातक कंपनियों पर इसका बहुत बुरा असर होगा। उस स्थिति में 13 बड़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को 360 अरब डॉलर मूल्य का नुकसान होगा।

दुनिया के बड़े निवेशक इस बदलती हकीकत को आकार दे रहे हैं। दिसंबर में 631 गैर अमेरिकी निवेशक जिनके पास 37 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, ने सरकार से कहा कि वह जलवायु संबंधी कदमों को गति दे। गत माह 7 लाख करोड़ डॉलर की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्लैकरॉक ने कहा कि वह उच्च स्थायी जोखिम वाले निवेश से बाहर निकलेगी। कोयले के साथ ज्यादा जोखिम कोयला कोयला भंडार का ब्युश्किल चोथाई हिस्सा दो डिग्री सेल्सियस वाली परिस्थिति में जलाया जा सकता है।

सन 2011 से अब तक कोयला खनन कंपनियों के मूल्य में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। कोयला उत्पादन बढ़ाने की घोषणाओं के बीच भारत को फंसी सुरक्षा तकनीक, आर्थिक या भूराजनीति से प्रभावित हुई है। अब इन सभी मोर्चों पर बदलाव हो रहे हैं। ऊर्जा की मांग भी पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है। पुरानी चिंताएं और नई समस्याएं घुलमिल गई हैं। भारत को आगे रहने की तैयारी रखनी होगी।

# विवाद से विश्वास के पीछे क्या है?

केंद्र सरकार की घोषित 'विवाद से विश्वास' योजना के माध्यम से राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह योजना लोगों का वह समय और पैसा बचाने में मदद करेगी जो ऐसे मामलों में जाया होता है। दरअसल करीब 9.3 लाख करोड़ रुपये के 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष कर संबंधी मामले विभिन्न स्तरों पर अपील में लंबित हैं। योजना के अनुसार यदि कोई करदाता चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर चुकाने को तैयार हो जाता है तो उसे ब्याज, जुर्माने और अभियोग से बचाव मिलेगा। करदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे 31 मार्च के बाद और 30 जून के पहले विवाद निपटा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसे वक्त पर विवादों को कम करने और संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है जब लग रहा है कि वह राजस्व लक्ष्य से काफी पीछे रह सकती है।

परंतु योजना को लागू करने का तरीका चिंता की वजह बन सकता है। इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अधिकारियों की सालाना वेतन वृद्धि को योजना के तहत किए जाने वाले संग्रह से जोड़? का निर्णय लिया है। सीबीडीटी कार्यालय के एक ज्ञापन के मुताबिक संग्रह के नतीजे भविष्य में इन अधिकारियों की तैनाती में भी अहम भूमिका निभाएंगे। यह विवाद निस्तारण योजना घोषित होने के तत्काल बाद विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वे शनिवार को और छुट्टी के दिन भी काम करें ताकि जब योजना की आधिकारिक शुरुआत की जाए तो वे तत्काल संग्रह शुरू

कर सकें। यह करदाताओं के शोषण का हथियार है। ऐसे में सरकार की इस मुद्दे से निपटने की शुरुआत ही गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह समाधान आवश्यक है कि इतने ज्यादा कर विवाद क्यों हैं? पहले तो सरकार राजस्व संग्रह के अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करती है और कर विभाग पर यह दबाव बनाती है कि वे ऐसी कर मांग करें जिसका करदाता प्रतिरोध करते हैं। इससे विवाद उत्पन्न होते हैं। अब प्रदर्शन के आकलन का नया लक्ष्य कर अधिकारियों को मजबूर करेगा कि वे

लक्ष्य के खिलाफ जाएंगे।

निश्चित तौर पर विवाद की समस्या को जड़ के जरिये ही हल किया जा सकता है। सरकार को जिम्मेदार ढंग से बजट तैयार करना होगा। वह अपने ताजा राजस्व स्तर के साथ लगातार मौजूदा ढंग से व्यय नहीं कर सकती। अति आशावादी राजस्व अनुमान न केवल करदाताओं की प्रताड़? की वजह बनते हैं बल्कि सरकार के व्यय में भी अनिश्चितता आती है। सरकारी विभाग भी सुनिश्चित नहीं हैं कि उन्हें वित्त वर्ष के आरंभ

पाम तेल इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अधिकारियों की सालाना वेतन वृद्धि को योजना के तहत किए जाने वाले संग्रह से जोड़? का निर्णय लिया है। सीबीडीटी कार्यालय के एक ज्ञापन के मुताबिक संग्रह के नतीजे भविष्य में इन अधिकारियों की तैनाती में भी अहम भूमिका निभाएंगे। यह विवाद निस्तारण योजना घोषित होने के तत्काल बाद विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वे शनिवार को और छुट्टी के दिन भी काम करें ताकि जब योजना की आधिकारिक शुरुआत की जाए तो वे तत्काल संग्रह शुरू कर सकें।

करदाताओं से विवादित राशि वसूल करने का हरसंभव प्रयास करें। यह स्वाभाविक रूप से शोषण की ओर ले जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि करदाता लोगों को बार-बार फोन कर रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह कि योजना की मामूली सफलता भी सरकार को ऐसी मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे विवाद बढ़ेंगे और फिर निस्तारण की पेशकश की जाएगी। इससे लागत बढ़ेगी और कारोबारी सुगमता प्रभावित होगी। यह सरकार के कर आतंक खत्म करने के घोषित

में आवंटित राशि व्यय करने के लिए मिलेगी या नहीं। सरकार को कर विवादों के तेज निस्तारण की दिशा में काम करना होगा। संभव है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में जहां कर कानून जटिल है, वहां विवाद भी होंगे। ऐसे में ऐसी व्यवस्था लागू करना होगी ताकि इन विवादों को समय पर निपटया जा सके। भारत को निजी निवेश के लिए इसलिए भी कठिन माना जाता है क्योंकि कर विभाग और करदाताओं के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ताजा कदम से समस्या बढ़ेगी।

## रुपहले पर्दे की उजली चमक में छिपे उम्मीद भरे सबक

### वनिता कोहली-खांडेकर

यह अच्छी खबरों का एक टुकड़ा भर है लेकिन इस पर टिके रहने लायक है। भारतीयों ने वर्ष 2019 में फिल्मों के कुल 1.03 अरब टिकट खरीदे। ऑगैक्स मीडिया बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक यह आंकड़ा वर्ष 2018 की तुलना में नौ फीसदी अधिक है जब 94.5 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई थी। यह वृद्धि बहुत अधिक न हो रही है। पहला, यह भारत के 1.67 लाख करोड़ रुपये के मीडिया एवं मनोरंजन बाजार के लिए खराब रहे साल का इकलौता उजला पहलू है।

आर्थिक सुस्ती, टेलीविजन प्रसारण के लिए चैनलों की कीमत तय करने का ट्राई का फैसला और इस उद्योग की वृद्धि एवं रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी व्यापक नीति का पूर्ण अभाव होने से वर्ष 2019 इस क्षेत्र के लिए निराशाजनक रहा। विज्ञापन राजस्वों में वृद्धि एक अंक में गिर चुकी है जबकि भुगतान राजस्व के मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी भी बड़े सूचीबद्ध मीडिया समूह- जी एंटरटेनमेंट, नेटवर्क18, जागरण प्रकाशन या डीबी कॉर्पोरेशन की तिमाही रिपोर्टों को देखें तो खबर अच्छी नहीं है। डिज्नी स्टार और टाइम्स ग्रुप जैसी हरेक बड़ी गैरसूचीबद्ध युग को लक्ष्य हासिल करने में जटिलता करनी पड़ रही है। अभी तक के साक्ष्य महज आख्यान हैं लेकिन नौकरियां तो गई हैं। ध्यान रखनी होगी।

### टी. एन. नाइदन

शायद सरकार का यह कहना सही है कि अर्थव्यवस्था उस निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है जहां से केवल सुधार की संभावना है। शुक्रवार को जारी आर्थिक वृद्धि के तिमाही आंकड़े इसका समर्थन करते हैं और निवेश बैंकों के अर्थशास्त्री भी मोटे तौर पर इसकी पुष्टि करते हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी यह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आने वाले वर्ष में भारत में मामूली सुधार देखने को मिलेगा। इस बात पर सहमति है कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है और मंदी भी अपना चरम चहुँक चुकी है। इससे सरकार के प्रवक्ताओं को प्रोत्साहन मिला है और वे यह कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक चक्रीय प्रकृत की मंदी से गुजरी और वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं ने संकट में इजाफा किया। उनका यह भी कहना है कि यह सिलसिला भी सुधार पर है। हमें ऐसे अनुमानों को लेकर सतर्क रहना होगा जो प्रमुख तौर पर घरेलू कारकों के आंशिक विश्लेषण पर आधारित है। मसलन

रखें कि टीवी एवं प्रिंट माध्यम मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के अगुआ हैं। टेलीविजन अकेले आधा राजस्व जुटाता है जबकि प्रिंट इस उद्योग का 18 फीसदी से अधिक राजस्व जुटाता है। जहां तक फिल्म उद्योग का सवाल है तो वह महज 10 फीसदी राजस्व ही ला पाता है।

और इसी बिंदु से हम दूसरे कारण तक पहुंचते हैं। करीब चार वर्षों से टिकटों की संख्या गिर रही थी या स्थिर बनी हुई थी जबकि औसत टिकट मूल्य लगातार बढ़ रहा था। बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या आम तौर पर 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ के बीच में थी। लेकिन मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष में भारत की शीर्ष तीन मल्टीप्लेक्स श्रृंखलाओं में तीन वर्षों के बाद टिकट बिक्री में उछाल देखने को मिली। ऑगैक्स की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर उछाल की पुष्टि करती है और दिखाती है कि 2019 में पूरे साल यह मजबूत बनी रही। मोटे रूझानों के हिसाब से देखें तो रिपोर्ट अधिक भाषाओं, बेहतर कहानियों और पहले सप्ताहांत पर निर्भरता कम करने पर जोर देती है जिससे यह वृद्धि आगे भी जारी रहे।

इनमें से सबसे अहम वह तरीका है जिससे भारत की विविधता आंकड़ों में नजर आ रही है। एक अरब से अधिक टिकटों की बिक्री और 10,948 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस राजस्व संग्रह हिंदी, तमिल, तेलुगु, हॉलीवुड और अन्य फिल्मों के बीच बंटा हुआ था। ऑगैक्स मीडिया के मुख्य कार्याधिकारी

शैलेश कपूर कहते हैं, 'कुल मिलाकर भाषा काफी अहम होती जा रही है। हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म साहो का 60 फीसदी से अधिक बॉक्स ऑफिस राजस्व हिंदी संस्करण से आया। इसी तरह हिंदी फिल्म वॉर का कुछ कारोबार तेलुगु संस्करण से भी आया। हम एक ऐसे परिदृश्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें शीर्ष दस में शामिल कई फिल्मों बहु-भाषाई हैं। हॉलीवुड फिल्मों का ही उदाहरण लेते हैं। इनकी राजस्व हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2018 में कुल बॉक्स ऑफिस संग्रह में हॉलीवुड फिल्मों का योगदान 12.5 फीसदी रहा था जो 2019 में बढ़कर 15 फीसदी हो गया। लेकिन इसकी वजह यह है कि हॉलीवुड फिल्मों को अब एक साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कुछ अन्य भाषाओं में भी डब कर रिलीज किया जा रहा है। इस बारे में कपूर कहते हैं, 'अवैजंस फिल्म का 40-45 फीसदी राजस्व हिंदी, तमिल एवं तेलुगु संस्करणों से आया। यह बात सभी फ्रैंचाइजी या बड़ी फिल्मों के लिए सही है। बिजली का औसतन 35 फीसदी राजस्व भारतीय भाषाओं से आता है।'

दूसरी भारतीय भाषाओं में डब या रीमेक हुई हिंदी फिल्मों के बारे में भी यही स्थिति है। यही हाल हिंदी में डब या रीमेक होने वाली गैर-हिंदी फिल्मों का है। बहुभाषाई फिल्मों के टिकट अधिक राजस्व के शीर्ष पर हैं। इस रिपोर्ट के अच्छी खबर होने का तीसरा कारण यह है कि अब अधिक लोग फिल्मों देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करने लगे हैं। फिल्म उद्योग के राजस्व का 70 फीसदी से अधिक राजस्व टिकट बिक्री से आने की वजह से यह काफी अहमियत रखता है। निश्चित रूप से फिल्मों की पहुंच एवं प्रभाव एक अरब टिकटों की बिक्री से बहुत आगे तक जाता है। कुल टीवी दर्शकों में से एक चौथाई लोग अपने घरों में फिल्मों देखते हैं। भारत में स्ट्रीमिंग वीडियो ब्रांड फिल्मों एवं फिल्म-संबंधी सामग्रियों पर असंगत रूप से अधिक वक्त देते हैं। लेकिन फिल्म उद्योग तो बुनियादी तौर पर बॉक्स ऑफिस से अपना पैसा कमाता है। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का यह मतलब है कि फिल्मों को खरीद सकते हैं कि अधिक लोगों के फिल्म देखने सिनेमाघर जाने का मतलब यह है कि देश में कोई आर्थिक सुस्ती नहीं है। यह एक दोषपूर्ण तर्क है। इसका कारण यह है कि अगर टिकट बिक्री ही देश की वृहद-आर्थिक सेहत का पैमाना है तो फिर हम इसके पहले के चार वर्षों में भारी मंदी के दौर से गुजर रहे थे।

के समकक्ष रखा है जबकि करीब दो दशक तक व्यापार वृद्धि की दर विश्व अर्थव्यवस्था से 40 फीसदी तक अधिक रही है। यह बदलाव आंशिक रूप से तो इसलिए है क्योंकि विभिन्न देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुए और उसके परिणामस्वरूप संरक्षणवाद लागू किया गया। परंतु इसकी अन्य वजह भी हैं। व्यापार जगत में शीघ्र सुधार की उम्मीद नहीं है। तीसरा कारक वह है जिसे विश्व बैंक उभरते बाजारों की उत्पादकता वृद्धि में कमी के रूप में दर्ज करता है। देश में यह एकदम स्पष्ट रूप से हमारे सामने है क्योंकि आर्थिक वृद्धि निवेश दर की तुलना में तेजी से गिरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत को अब समान वृद्धि दर हासिल करने के लिए पहले की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता है। आखिर में वे जोखिम आते हैं जो वैश्विक कर्ज से संबंधित हैं। इससे मुद्रा बाजारों में असामान्यता आ रही है क्योंकि निवेश दर ऋणात्मक है। भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें झटके लगने की ज्यादा आशंका है।

## आने वाला समय वेब 3.0 का है जिसमे हर लेनदेन डिजिटल होने वाला



ममता मर्डी

(आर्थिक वेन ब्लॉक से जुड़ी हैं।)

आने वाला समय (भविष्य) वेब 3.0 और अक का है। समय रहते जो अपने आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू कर लेगा उसको नई नौकरी पाने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और जो अभी नौकरी कर रहा है उसको अपनी नौकरी जाने का डर नहीं रहेगा क भविष्य में जब हर चीज वेब 3.0 ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो चुकी

होगी तो आज जो लोग अपने को भविष्य की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं कर रहे होंगे वो लोग शायद हाशिए पर चले जाएंगे क बेशक आज हम किसी भी कारणवश (डर, अज्ञानता या अन्य किसी भी कारण) से आज टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी से कभी भी कट करके नहीं रह सकते हैं बिलकुल वैसे ही जैसे हम मानव समाज और कुदरत से कट करके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं कभविष्य टेक्नोलॉजी का है; बेशक आज हम भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझते नहीं या समझना नहीं चाहते है लेकिन टेक्नोलॉजी फिर भी हमें प्रभावित कर रही होती है |आज हमारा दिन-रात पल-पल

वेब 2.0 में गुजर रहा है क आज हमारा इंटरनेट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर डिजिटल एक्टिविटी वेब 2.0 पर चल रही है लेकिन आने वाला समय वेब 3.0 का है जिसमे हर लेनदेन डिजिटल होने वाला है। आज दुनिया का हर सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट (एजुकेशन, मेडिकल, बैंकिंग, ट्रेवलिंग अत्यादि-अत्यादि) ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट के प्रोसेस में है और आनेले 1.5 वर्ष तक सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा ब्लॉकचेन अभी तक की सबसे सेफएस्ट, सिक्नोर और फास्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ही डीसेन्ट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ है मतलब क्रिप्टो करेंसी का बेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है। मीथर का एम क्वार्टिन 3.0 क्रिप्टो करेंसी है जो 2.5 वर्ष पहले केवल 8 सेंट से

शुरू हुआ था और आज 83% गुणा ग्रोथ के साथ 2.5 डॉलर का है। भविष्य में वेब 3.0 वाली करेंसी ट्रेड और ट्रेड में रहेगी इसलिए आज जो समय रहते ही 3.0 क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लेंगे भविष्य में वो यकीनन बहुत अच्छा रिटर्न पा सकेंगे। साथियों, ही 3.0 क्रिप्टो करेंसी एम काइन का स्टेकिंग समय 2 और 2.5 वर्ष है जो 31 जुलाई से 2.5 वर्ष और 3 वर्ष होने वाला है। एम क्वार्टिन के प्राइस और कंपनी की अभी की ऑफर के हिसाब से सबसे छोटे पैकेज (11400 रूपए) में ज्वॉइनिंग से लेकर आप भी मीथर वर्ल्ड में काम कर सकते हैं और फैनैशियल फ्रीडम के साथ साथ अन लिमिटेड इनकम भी प्राप्त कर सकते है, वो भी बिना किसी लायबिलिटी के। (संपर्क 8789963383)



# संवेदक से 10 लाख लेवी मांगने वाले दो अपराधी गिरफ्तार

## खबर मन्त्र संवाददाता

**किस्को।** किस्को थाना पुलिस ने संवेदक से 10 लाख रुपया के लेवी मांगने के दो आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से तीन मोबाइल भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ बीएन सिंह ने बताया कि किस्को थाना क्षेत्र में निमाणाधीन एकलव्य मॉडल रेसिडेन्सियल स्कूल खरकी बालाटोली, किस्को के मुख्य गेट पर

झारखंड प्रस्तूती कमिटी (जेपीसी) निवेदक- सब जोलन कमाण्डर अभिमन्यू जी के नाम पर पचास टकर एवं मुंशी के मोबाइल फोन पर दस लाख का लेवी मांगने के संबंध में किस्को थाना काण्ड स0-22/2023, दिनांक-10.07.2023, धारा-387/506 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के निर्देशन में कांड के उदभेदन सल्लिप्त अपराधकर्मा के गिरफ्तारी हेतु अपर



गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस अधिकारी

पुलिस अधीक्षक (अभियान) लोहरदगा एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी लोहरदगा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर कांड में

सल्लिप्त दो अपराधकर्मा को तकनिकी शोके के सहयोग से काण्ड में प्रयुक्त मोबाइल फोन एवं सीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किये तथा अन्य सहयोगी का नाम बताया जिसकी गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम के द्वारा अभियान जारी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक कीपैड मोबाइल काण्ड में प्रयुक्त मो०न०-8084361527 के साथ 02. ओपों

कम्पनी का एंड्रॉयड मोबाइल दो सिम के साथ। 03. रीलमे नोट 7 प्रो मोबाइल बरामद किया गया। वही गिरफ्तार अपराधियों में अभिमन्यू जी उर्फ कुन्दन तिवारी उर्फ आशुतोष कु० तिवारी उम्र 26 वर्ष पिता-पुरुषोत्तम तिवारी, ग्राम-सिन्दूरिया लहलहे, थाना-सतबरवा, जिला-पलामू निवासी और मुबारक अंसारी उम्र 20 वर्ष पिता-बुल अंसारी, सा०- सेमरडीह, थाना-किस्को शामिल है।

## सड़क-पुल के अभाव में मरीज को पीठ पर लादकर अस्पताल लाने को मजबूर हुए ग्रामीण

### लघर द्यावस्था

- बाँदा पंचायत अंतर्गत लुकुईया गांव के तेतरियाटांड का मामला
- समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाने के कारण हो गई थी मौत

## खबर मन्त्र संवाददाता



मरीज को पीठ पर लादकर ले जाते हुए ।

**चंदवा।** प्रखंड के बोदा पंचायत अंतर्गत लुकुईया गांव के तेतरियाटांड टोले तक पहुँच पथ के सिरताही नदी पर पुल नहीं बनने के कारण पंचायत समिति सुशीला तोपनो के ससुर सिमोन तोपनो के समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाने के कारण मौत होने का मामला उंडा भी नहीं पड़ा था कि घटना के महज 48 घंटे के अंदर गांव से ही एक और मामला सामने आ गया जहां परिजनों व ग्रामीणों को एक वृद्ध बीमार महिला को इलाज के लिए पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए लगभग एक किलोमीटर पैदल लाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि सुचिता भेंगरा पति सुधीर तोपनो लकवा ग्रस्त है, उनकी तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई। सड़क के खराब होने व सिरताही

नदी पर पुल नहीं होने के कारण मरीज को अस्पताल लाने के लिए परिजनों व ग्रामीणों को एक बार फिर से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तबीयत ज़्यादा खराब होता देख परिजन व ग्रामीण साहस का परिचय देते हुए सुचिता भेंगरा को पीठ पर लादकर पैदल लुकुईया तक पहुँचे, इसके बाद निजी वाहन से मरीज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, अगर ग्रामीण साहस का परिचय ना देते तो सुचिता भेंगरा को पीठ पर लाद कर नहीं लाते तो उसकी भी जान नहीं बच पाती।

## बुंडू में नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह

### जन सुरक्षा और न्याय पहली प्राथमिकता : डॉ विमल कुमार

## खबर मन्त्र संवाददाता

**बुंडू।** पीडित जनता सुरक्षा और न्याय के लिए पुलिस के दरबार में आती है जिस पर सहारा नहीं मिलता तो लोग पुलिस प्रशासन को कोसते है। इसी कारण पुलिस और जनता के बीच फासला बढ़ती है जिसको पाटने की जरूरत है उक्त बातें सरायकेला खरसावाँ जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने कही वह बुंडू के बालाजी प्लेस में शुक्रवार को एक नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा जो भी पुलिस पदाधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसे कार्रवाई की जाएगी। जनता के सुख दुख का साथी बनकर पुलिस काम करें तो समाज में शांति सद्भावना बनी रहेगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा



जनता के सेवा सुरक्षा और न्याय के लिए आईपीएस अधिकारी बनाया गया है। खतन की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर झारखंड अधिविध परिषद के सदस्य और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ राधा रमन साहू ए प्रिंसिपल डॉ अरुण कुमार, डॉ मदन प्रसाद डॉ पंकज वर्मा ए डॉ ईला वर्मा ए पुलिस काम करें तो समाज में शांति सद्भावना बनी रहेगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा

प्रखंड प्रमुख अजय कुमार मुंडा ए जिला परिषद सदस्य परमेश्वरी शांडिल ए नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल ए महेंद्र प्रजापति ए छोट्टे जायसवाल ए अधिवक्ता रितेश जायसवाल ए प्रमोद कुमार सिंह ए कमलेश सिंह ए अन्वु सईद अंसारी ए कवि नायक ए उज्ज्वल कुमार धीवर ए खुशी लायक ए संजय दास ए मनीष जायसवाल के अलावा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानेदार पुलिसकर्मी और गणमान्य लोग मौजूद थे।

## भूमि के बेहतर प्रबंधन से होगा वन उत्पादकता में सुधार



## खबर मन्त्र संवाददाता

**पिस्कानगड़ी।** नगड़ी के लालगुटवा स्थित वन उत्पादकता संस्थान और जैव विविधता संस्थान हैदराबाद के सौजन्य से वन की उत्पादकता में सुधार और निम्नीकृत भूमि प्रबंधन के माध्यम से आजीविका का सृजन विषय पर अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते निदेशक डॉ योशिवर मिश्रा ने कहा परती भूमि में विकास के द्वारा जीविकोपार्जन पर चर्चा की जाएगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक देवीदत्त बिस्वाल ने जीविकोपार्जन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा उत्पादकता में सुधार वन भूमि प्रबंधन पर्यावरण वाचक की एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों की पारिस्थितिकी सुधार आदि कार्यों को जीविकोपार्जन से जोड़कर

**रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक में समस्याओं पर चर्चा**  
**पिपरवार।** रैयत विस्थापित मोर्चा और सीसीएल प्रबंधन के बीच विभिन्न मांगों को लेकर सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई इस बैठक में सीसीएल के सभी कमांड क्षेत्रों के विस्थापित/प्रभावित/रैयतों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में लम्बित नौकरी ए मुआवजा/परोजगार/एनजी कम्पनियों मे 75 प्रतिशत बहाली/एक करोड़ तक का टेका कार्य विस्थापितों को देने सहित कई ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मॉडल बनाने का आग्रह किया। इन्होंने जैविक खाद/एम्बल्ली पालन को बढ़ावा देकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर बल दिया।

## सेल के संयंत्रों में कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने को समझौता

**बोकारो।** सेल ने बोकारो सहित सभी संयंत्रों में टिकाऊ इस्पात उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जर्मनी की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एसएमएस ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सेल के रांची स्थित प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में बदलाव लाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के

अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर देना है। साझा विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, सेल और एसएमएस समूह पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन का एक नया प्रतिमान स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इससे स्टील निर्माण प्रक्रिया में सेल के इस्पात संयंत्रों के भीतर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है।

## गर्म ओबी से झुलसी छात्रा की मौत

### सुनील सिंह

**झरिया।** बीसीसीएल के लोदना क्षेत्र में चल रहे सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना से हो रहे गर्म ओबी के चपेट में शौच ले लिए गयी एक महिला व बच्ची आ गयी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए एस एन एम एससीएच अस्पताल ले जाया गया। जहां कि बनिवहीर 2 नंबर मैदान के समीप ओबी डंप के गर्म छाई से झुलसी 11 वर्षीय कक्षा पांच की छात्रा जिया कुमारी की मौत गुरुवार

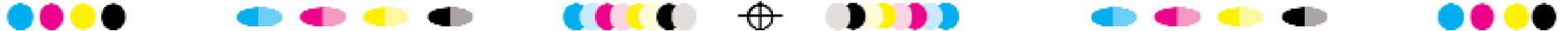
### पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी छात्रा



थी। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आज जिया के साथ हुआ, तो कल हमारे बच्चों के भी साथ इस तरह की घटना हो सकती है। सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।

की देर रात हो गयी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिया का इलाज एसएमएसएमसीएच में चल रहा था।

परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे। परंतु 11 वर्ष की बच्ची जलन व दर्द नहीं झेल



## एक नजर में

### संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत

**गढ़वा।** शहर के सोनपुरवा भट्टी मोहल्ला निवासी रविंद्र कुमार कुशवाहा की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। गढ़वा थाना क्षेत्र के नारायणपुर में उसका शव बरामद किया गया है। परिजनों ने इस घटना में हत्या का आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रविंद्र गुरुवार की देर शाम नारायणपुर में 11 नं रोपने के लिए मजदूर खोजने गया हुआ था। मजदूर खोजने के बाद लौटने के क्रम में उसे सड़क किनारे गिरा हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल लाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पिछले काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है। उक्त विवाद में रविंद्र की हत्या की गई है। साक्ष्य छुपाने के लिए इसे दुर्घटना का रूप दिया गया है।

### दुर्घटना में बीडीसी के पुत्र की मौत

**मझिआंव।** थाना क्षेत्र के चंदना गांव निवासी करमडीह पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मशरुन खातून (पति मसिउदीन खान) के पुत्र अली रजा की शुक्रवार को रांची स्थित रिम्स अस्पताल में मौत हो गई। वह पिछले दस दिनों से जीवन और मौत के बीच झुल रहा था। विदित हो कि पिछले बुवार को गढ़वा जाने के दौरान खजुरी गांव स्थित नदी के पुल पर उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई थी। इसके बाद उसे रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच मोहरम के दिन चिकित्सक ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह चंद घंटे का ही मेहमान है। इसके बाद उसके परिजनों द्वारा घर लाया जा रहा था, इसी बीच गढ़वा के समीप उसके शरीर में हरकत होता देख परिजनों ने उसे परमेश्वरी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जहां पर उसे वेंटिलेटर पर दो दिन रखने के बाद रांची स्थित रिम्स में रेफर कर दिया गया था और उसकी रिम्स में कोमा की ही स्थिति में शुक्रवार को मौत हो गई। उसकी मौत पर मुखिया मोस्सरत जहां एवं उनके प्रतिनिधि ईंतखाब खान, शाहबाज खान, सोनपुरवा मुखिया अख्तर खान, असफाक खान, इब्रार खां सहित प्रखंड के सभी बीडीसी सदस्य व मुखिया द्वारा शोक व्यक्त किया गया है।

### बाजार और जतराटांड की भूमि पर अवैध

#### कब्जा के खिलाफ उपायुक्त को लिखा पत्र

**खलारी।** हेसालोंग ग्राम के ग्रामीणों ने खलारी प्रखंड के लपरा पंचायत अंतर्गत हसालोंग में बाजार टॉड स्थित बाजार टॉड की जमीन पर अवैध कागजात बनाकर कब्जा करने के मामले पर रांची उपायुक्त को लिखा पत्र। पत्र में बताया गया कि हेसालोंग बाजार टॉड में बाजार एवं मेला टॉड की जमीन जो मौजा हेसालोंग खाता नं 78 79 प्लॉट नं 747ए 748 रकबा 0७62 एकड़ 1७36 ए 0७01 ए० कुल रकबा 1७99 एवं किस्म परती कदमी खतियान मैरमजरूआ के तहत निर्बंधित है। साथ ही खतियान में यह भी दर्शाया गया है कि उक्त जमीन पर शुक्रवार को बाजार व प्रतिवर्ष मेला लगता है। साथ ही उक्त बाजार से सरकारी जमीन पर आदिवासियों मूलवासियों के लिए बानस्थलए दुर्गामण्डपए हजामन मंडप का निर्माण हुआ है जो गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र है। इन लोगों को हेसालोंग बाजार जमीन को खाली करने में सचिवालय रांचीएभू अर्जन पदाधिकारी रांचीएडीसीएलआर रांचीएअपर समाहर्ता रांचीएअनुमंडल पदाधिकारी रांचीएबन्वेस्टमेन्ट पदाधिकारी रांचीएप्रवर्तन निदेशालय रांची को दिया गया प्रतिलिपी।

### मृत महिला को विधायक ने दी श्रद्धांजलि

**राह।** प्रखंड के होटलो पंचायत के अंतर्गत कावोडीह गांव के आजसू कार्यकर्ता वनमाली महतोए इन्द्र महतो व ब्रज महतो की माता 73 वर्षीय बुद्धि देवी को 22 जुलाई को जंगली भालू के हमले से मौत हो गया था। इनके श्राद्धकर्म में विधायक सुदेश महतो कापीडीह गांव पहुँचकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किये और परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट किये। मौके पर प्रखंड प्रभारी संजय सिद्धार्थ, प्रखंड अध्यक्ष रंग बहादुर महतो, मीडिया प्रभारी हलधर पांडेय मौजूद थे।

### कांके : कांग्रेस सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष

#### साबिर अंसारी पदमुक्त

**कांके।** रांची जिला ग्रामीण सेवा दल के जिला अध्यक्ष अमजद अंसारी ने इरवा ओरमांझी निवासी जिला उपाध्यक्ष साबिर अंसारी को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया है। इस बाबत इन्होंने कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष नेली नाथन को सूचना दे दी है। अमजद अंसारी ने प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा है कि साबिर अंसारी जब से जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वह लगातार पार्टी विरोधी गलत गतिविधियों में लिप्त है। जिससे पार्टी व संगठन की छवि खराब हो रही थी। 4 दिनों पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रदा आहत राजभवन के समक्ष हुए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भी इन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया था। पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता को देखते हुए इन्हें जिला उपाध्यक्ष पद से पद मुक्त किया गया है।

### इंटर के नये प्रमारी का शिक्षकों ने किया स्वागत



**बेड़ो।** करमचंद भगत महाविद्यालय बेड़ो के इंटरमीडिएट प्रभाग के नवनि्युक्त प्रभारी पुनम कुमारी का शुक्रवार को शिक्षकों ने बूके देकर स्वागत किया। प्रभारी ने कहा कि इस महाविद्यालय में इंटरमीडिएट प्रभाग के बेहतर संचालन के लिए अनुशासन व नियमित कक्षाओं की सुनिश्चितता मेरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं मौके पर शिक्षकों में शिवेंद्र सौरभ ए आशीष भारतेन्दु, शिवशंकर साहू, ब्रिसा उरांव, मधुमति उरांव, कृति निधि कुमारी व संतोषी कच्छप आदि मौजूद थे।

### बेड़ो : भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बीड़ओ से मिला



**बेड़ो।** भाजपा का प्रतिनिधिमण्डल शुक्रवार को बेड़ो के बीड़ओ सुनील कुमार केशरी से मिला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मॉडल स्कूल बेड़ो के शिक्षक भिंसेंट सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका स्थानांतरण करने की मांग किया। भाजपा महामंत्री राजेश साहू व बलराम सिंह ने बताया कि मॉडल विद्यालय बेड़ो के शिक्षक भिंसेंट सोरेन के द्वारा गत दिनों छात्रों को तिलक लगाकर विद्यालय आने पर प्रताड़ित किया गया था। जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त था। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुनील कुमार केशरी से मिलकर विरोध जताया। साथ ही शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए अतिबंध स्थानांतरण करने की मांग किया। जिससे विद्यालय की छवि खराब न हो। मौके पर पूर्व 20 सुनील अध्यक्ष राजीव रंजन अधिकारी मंडल अध्यक्ष आलोक मिश्राए जिला परिषद पूर्वी के प्रतिनिधि जगननाथ भगतए भाजपा ग्रामीण रांची जिला एस टी मोर्चा उपाध्यक्ष भीखा उरांव मौजूद थे।





मणिपुर पर भारी हंगामे के बीच लोकसभा में दो विधेयक पारित

# सैन्य सेवाओं में अनुशासन बढ़ेगा : राजनाथ

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच द इंटर सर्विसेज आर्गनाइजेशन (कमांड कंट्रोल एंड डिसिपलिन) विधेयक 2023 और भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित किये गये। इस दौरान विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सदन में आकर वक्तव्य देने की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी करते रहे। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाकर इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग लें। इसके बाद भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द इंटर सर्विसेज आर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिपलिन) विधेयक 2023 को पेश करते हुए कहा कि यह सेना के तीनों सेवाओं में अनुशासन बनाने में मददगार होगा। कर्माडिंग ऑफिसर या कर्माडिंग इन चीफ तीनों सेनाओं के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस विधेयक से सैन्य बलों पर कोई विधेयक भार नहीं पड़ेगा।



यह विधेयक सेना अधिनियमों में किसी तरह का बदलाव भी नहीं करता। स्थायी समिति ने बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि इसके माध्यम से प्रबंधकीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस विधेयक में मुम्बई के एक संस्थान को भारतीय प्रबंधन संस्थान का दर्जा देने के

## राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित

राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां राज्यसभा की स्थिति तो वहीं विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की जोरदार तरीके से मांग की जिसके कारण हुए हंगामे के चलते एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह के स्थगन के बाद सभापति जगदीप धनखंड ने 12 बजे जब कार्यवाही शुरू की तो भाजपा के घनश्याम तिवारी ने राज्यसभा में एक किशोरी के साथ बर्बरता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति कायम रखने में विफल रही है और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। नेता सदन पियूष गोवाल ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है और सभापति को तुरंत राज्यसभा की स्थिति पर सदन में चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खडगे ने कहा कि विपक्ष पिछले कई दिनों से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

प्रावधान किये गये हैं। इसके माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान में एकरूपता लायी जा सकेगी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस दौरान विपक्षी सदस्य हाथों

## सदन में ललन को शाह ने खूब सुनाया

नयी दिल्ली, पटना।

दिल्ली वाला बिल तो लोकसभा से पास हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अब इस बिल को राज्यसभा में लाया जायेगा। इस बिल पर चर्चा में कुल 26 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल रहे। मगर जब मौका अमित शाह को मिला तो चारा घोटाले की याद दिला दी। पहले बिल के बहाने ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। लोकलाज से लेकर संघीय ढांचे तक की दुहाई दी। मगर दिल्ली वाला बिल पास हो गया, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जायेगा। बिल के खिलाफ बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि जो आप लेकर आए हैं, वो संघीय ढांचे पर आघात है। लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने लोकतंत्र को समाप्त करने



का काम किया है। ललन सिंह ने नसीहत दी कि लोकतंत्र, लोकलाज से चलता है।

**शाह ने दिला दी चारा घोटाले की याद :** अमित

शाह की बारी आयी तो उन्होंने इतिहास की याद दिला दी। अमित शाह ने कहा कि राजीव रंजन जी ने कहा था कि लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी लोकलाज तो आप मत ही बोलिए क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गये थे, आज चारा घोटाला करनेवालों के साथ आप बैठे हैं। फिर गढ़बंघन किये हैं। लोकलाज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगाता। जदयू का जन्म ही राजद के विरोध करने के लिए हुआ। गृहमंत्री अमित शाह के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर दिखा। अमित शाह ने ललन सिंह के सामने भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे प्रश्न उठा दिए हैं जिसका जवाब शायद जेडीयू के नेता दे पायें।

पीठासीन अधिकारी श्री अग्रवाल ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जायें और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें।



**बच्चों की बचत से सभी दंग 16 करोड़ की राशि इकट्ठा की** हिमनाथनगर। साबरकांठा जिले की इडर तहसील के 18 साल तक के बच्चों ने वह कर दिखाया है जो बड़े-बड़ों के लिए प्रेरणा बन जाए। यहां के बालकों ने अपने चॉकलेट, आइसक्रीम और अन्य उपहारों के पैसों की बचत कर अनूठी मिसाल पेश की है। सहकारिता के तहत इडर की बाल गोपाल मंडली में 5 करोड़ की रकम जमा की गई है। यह पूरी राशि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बचत है। केन्द्रीय मंत्री परसोतम रूपाला ने लोकसभा में बच्चों की इस कोशिश की सराहना की है। साबरकांठा जिले की इडर स्थित बाल गोपाल मंडली में 17 हजार बालक सदस्य हैं। इन बच्चों ने अब तक करीब 16 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अभी इनके बाल बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा हैं। साबरकांठा जिले के इन बच्चों ने इस धारणा गलत साबित कर दिया है कि वे रुपए का महत्व नहीं समझते।

## शिक्षक ही गुणवत्तापरक शिक्षा की धुरी हैं : मंत्री

देहरादून। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता की धुरी हमारे शिक्षक ही हैं। हमारी सरकार में गुरुजनों को पूरा सम्मान दिया जाता है। उनके शिक्षण व बच्चों के भविष्य निर्माण की प्रतिबद्धता से ही शिक्षा के मूल उद्देश्यों को हासिल किया जा सकेगा। शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय सभागार में आयोजित बैठक में राजकीय शिक्षक संघ के नव निर्वाचित प्रांतीय पाधिकारियों को बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो भी संभव होगा उसे पूरा किया जाएगा।

## भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन से सतक होगा राष्ट्र : शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन से देश सशक्त होगा। मोदी सरकार भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के सामने पांच प्रण रखे हैं। जिनमें से दो प्रण हैं- विरासत का सम्मान और गुलामी के चिन्हों को मिटाना है। इन दोनों प्रण के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए सभी भारतीय भाषाओं और राजभाषा को अपनी शक्ति दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि विरासत का सम्मान भाषा के समान के बिना अधूरा है और राजभाषा की स्वीकृति तभी आएगी जब हम स्थानीय भाषाओं को सम्मान देंगे। हिन्दी की सर्वांगीय स्थानीय भाषाओं से नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने

## पापुआ न्यू गिनी पहुंचे भारत के दो जहाजों की मारापे ने की मेजबानी



**नई दिल्ली (हि.स.)।** भारतीय नौसेना के चार जहाज इस समय विदेशी मिशन पर हैं। पूर्वी हिंद महासागर में तैनात भारत के जहाज आईएनएस सद्गाद्री और आईएनएस कोलकाता पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) में पोर्ट मोरेस्बे पहुंचे। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने भारतीय राजदूत इनबासेकर सुदामूर्ति के साथ जहाज का स्वागत करके मेजबानी की। इसी तरह ओमान की यात्रा पर गए आईएनएस

विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकेंद रायल नेवी के साथ समुद्री अभ्यास किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने डुकुम बंदरगाह का दौरा किया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सद्गाद्री पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) पहुंच गए हैं। यहां पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने कैबिनेट सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ जहाजों का स्वागत किया।

## राहुल मामले में सुप्रीम कोर्ट में जर्जों ने कहा

एजेंसी

**नयी दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की (न्यायमूर्ति वीआर गर्वा, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार) की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने मानहानि के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो साल की कैद की सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका बयान गुड टेस्ट में नहीं था। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देने समय सावधानी बरतने की उम्मीद

## बरान गुड टेस्ट में नहीं था, पर दो साल कैद की सजा का कारण नहीं



की जाती है। जैसा कि इस अदालत ने अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) अधिक सावधान रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा अधिकतम दो साल की सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम निर्णय अभी तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक

## तीन दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी

**नई दिल्ली (हि.स.)।** लगातार तीन दिन तक गिरावट का सामना करने के बाद आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। बाजार ने आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ की थी। दिनभर के कारोबार में कई बार विक्रवाली का दबाव भी बनता नजर आया, लेकिन खरीदारी के सपोर्ट से संसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक लगातार हरे निशान में बने रहे। दिनभर की खरीद बिक्री के बाद संसेक्स 0.74 प्रतिशत और निफ्टी 0.70 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। शुक्रवार के कारोबार में आईटी सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी होती रही। इसी तरह सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी खरीदारी का रुख बना रहा। दूसरी ओर रिजल्टी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑटोमोबाइल और पावर



सेक्टर के शेयरों में बिक्रवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी शुक्रवार को खरीदारी का जोर बना रहा। इसकी वजह से बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.65 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। शुक्रवार के कारोबार में आई तेजी के कारण बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गया। पूरे दिन के कारोबार के बाद बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ कर 304 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

## पाकिस्तान में नौ अगस्त को भंग होगी नेशनल असेंबली

**इस्लामाबाद (हि.स.)।** पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नौ अगस्त को भंग कर दी जाएगी। मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार रात यह घोषणा अपनी सरकारी आवास में की। यह निर्णय संसद सदस्यों के सम्मान में रात्रिभोज में संसदीय नेताओं से मुलाक़ात के बाद लिया गया। रात्रिभोज में प्रधानमंत्री शहबाज ने सभी से कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था पर चर्चा की। नौ अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भेजेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, विघटन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करने होंगे। अगर किसी भी कारण से



राष्ट्रपति सलाह पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो असेंबली खुद ही भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज ने आश्वासन दिया कि विश्व के साथ तीन दिनों के परामर्श के बाद वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम राष्ट्रपति को सौंपेगा। हालांकि, इस पर अमर कोई समझौता नहीं होता है, तो पाकिस्तान चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा और प्रस्तावित नामों में से कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार को नामित करेगा।

## स्टेट बैंक का मुनाफा डबल से भी हो गया ज्यादा

**नई दिल्ली (हि.स.)।** देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में एसबीआई का मुनाफा दो गुना से ज्यादा हुआ और यह बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली में बैंक को 6,068 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ दो गुना से ज्यादा उछलकर 16,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 6,068 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक ने कहा कि उसके बेहतर प्रदर्शन में खराब ऋणों में कमी और ब्याज आय में सुधार का विशेष योगदान रहा। एसबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 1,08,039 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 74,989 करोड़ रुपये रही थी। इस दौरान बैंक की कुल आय भी बढ़कर 1,32,333 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 94,524 करोड़ रुपये रही थी।



मास्को। रूस के ऑनलाइन समाचार आउटलेट एस्ट्रा ने शुक्रवार सुबह नोवोरोसिस्क के रूसी काला सागर बंदरगाह के पास विस्फोट और गोलीबारी की आवाज सुने जाने की खबर प्रसारित की है। एस्ट्रा ने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में समुद्र की दिशा से आने वाली गोलियों की आवाज के साथ टट से कुछ दूर जहाजों की आवाजाही नजर आ रही है। यह काला सागर के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नोवोरोसिस्क की आपातकालीन सेवाओं ने विस्फोटों की पुष्टि की है। इस संबंध में देश की सुरक्षा सेवाओं को सूचित किया गया है। एक अन्य मीडिया संस्थान के अनुसार बंदरगाह ने अस्थायी रूप से सभी जहाजों की आवाजाही को रोक लगा दी है।

**VERMA PRESS**

**वर्मा प्रेस प्रा० लि० राँची**

**Verma's Today**

शृंखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं-

Class - X	Class - IX
• Hindi ₹ 140	• Hindi ₹ 140
• English ₹ 140	• English ₹ 140
• Mathematics ₹ 140	• Mathematics ₹ 140
• Science ₹ 140	• Science ₹ 140
• Social Science ₹ 140	• Social Science ₹ 140
• Sanskrit ₹ 120	• Sanskrit ₹ 120
• Hindi - B ₹ 140	• Hindi - B ₹ 80
• Hindi Vyakaran - I ₹ 120	• Hindi Vyakaran - I ₹ 120
• English Grammar - I ₹ 120	• English Grammar - I ₹ 120
• Sanskrit Vyakaran - II ₹ 100	• Sanskrit Vyakaran - II ₹ 100
• Hindi Practical ₹ 55	• Hindi Practical ₹ 55
• English Practical ₹ 55	• English Practical ₹ 55
• Maths. Practical ₹ 65	• Maths. Practical ₹ 55
• Science Practical ₹ 65	• Science Practical ₹ 70
• S. Science Practical ₹ 65	• S. Science Practical ₹ 65
• Sanskrit Practical ₹ 55	• Sanskrit Practical ₹ 55
• Maths. Practical (Combined) ₹ 90	• Maths. Practical (Combined) ₹ 75
• Science Practical (Combined) ₹ 90	• Science Practical (Combined) ₹ 75
English Medium	
• Mathematics ₹ 200	• Mathematics ₹ 130
• Science ₹ 200	• Science ₹ 200
• Social Science ₹ 200	• Social Science ₹ 130
• Maths. Practical ₹ 80	• Maths. Practical ₹ 80
• Science Practical ₹ 80	• Science Practical ₹ 80
• S. Science Practical ₹ 80	• S. Science Practical ₹ 80

मिलते-जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान !

